

प्रेषक,

आलोक कुमार,  
सचिव, मुख्यमंत्री  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

लोक शिकायत अनुभाग-5,

लखनऊ: दिनांक 25 अक्टूबर, 2021


विषय: जनसुनवाई-समाधान प्रणाली (IGRS) के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि जनसुनवाई-समाधान प्रणाली पर अधीनस्थों से प्राप्त आख्याओं का रैंडम आधार पर श्रेणीकरण, उच्चाधिकारियों द्वारा शासनादेश संख्या-1/2020/129/चौंतीस-लो०शि०-05/2020 दिनांक 17 फरवरी, 2020 एवं शासनादेश संख्या-540/चौंतीस-लो०शि०-05/2021 दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जा रहा है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त श्रेणीकरण की कार्यवाही अब प्रत्येक माह की 1 तारीख से 25 तारीख तक ही की जा सकेगी। प्रत्येक माह की 26 तारीख से अन्तिम दिवस तक श्रेणीकरण का कार्य नहीं किया जा सकेगा, इस हेतु IGRS प्रणाली में व्यवस्था निर्मित कर दी गई है।

3- अतः अनुरोध है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

  
(आलोक कुमार)  
सचिव।